

No. 7-9/2016-PCC  
Government of India  
Ministry of Communications  
Department of Posts

Dak Bhawan, Sansad Marg,  
New Delhi - 110001  
Date : 18.10.2016


To

All the Heads of Circle

**Subject: - Implementation of Government's decision on the recommendations of Seventh Central Pay Commission - Clarifications regarding.**

I am directed to re-circulate the following Office Memoranda issued by Ministry of Finance, Department of Expenditure, New Delhi on the subject noted below, for information and necessary action.

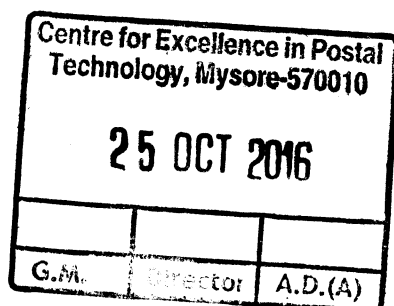
S/No.	Office Memorandum	Subject
1.	OM No. 12(1)/E.II (A)/2016 dated 07.10.2016	Grant of Advances - Seventh Pay Commission recommendations - Amendment to Rules of Compendium of Rules on Advances to Government Servants.
2.	OM No. 12(1)/E.II (A)/2016 dated 07.10.2016	Grant of advances- Seventh Pay Commission recommendations - Amendment to Rules 21 (5) of Compendium of rules on Advances to Government Servants.

  
(R.L. Patel)  
Asstt. Director General (GDS/PCC)

Encl : As above

Copy to :-

1. Chief General Manager, PLI/BD Directorate, New Delhi.
2. Addl. Director General, Army Postal Corps, R.K. Puram, New Delhi - 110066.
3. Director, RAKNPA, Ghaziabad,
4. DDG (PAF)/JS&FA/ Secretary (PSB)
5. All Directors/Dy Director of Accounts (Postal)
6. Pr. Director of Audit (Postal), Delhi - 110054.
7. The Officer In-Charge, APS Record Office, Kamptee.
8. All Directors, Postal Training Centers.
9. All Recognized Unions/Associations/Federations
10. Sr. PPS to Secretary (Posts) / DG (Posts).
11. All Members / DDGs
12. Resident Auditor, Postal Directorate.
13. C&A (PB), PAP, GA (Admin), SPG/PE-I/PE-II.
14. Director, CEPT, Mysore - for uploading on the official website of the Department.



No. 12(1)/E.II(A)/2016  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Expenditure

New Delhi, the 7<sup>th</sup> October, 2016

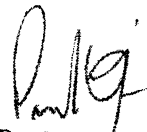
OFFICE MEMORANDUM

Subject: Grant of advances - Seventh Pay Commission recommendations- Amendment to Rules of Compendium of Rules on Advances to Government Servants.

The undersigned is directed to say that in pursuance of the decision taken by the Government on the Seventh Pay Commission's recommendations relating to advances, all the interest free advances stand discontinued as per attached annexure, with the exception that the interest free Advances for Medical Treatment, Travelling Allowance for family of deceased, Travelling Allowance on tour or transfer and Leave Travel Concession shall be retained.

2. In addition, the advance for training in Hindi through Correspondence Course, which is not mentioned in the Compendium of Rules on Advances to Government Servants, also stands abolished in pursuance of the decision of Government on 7<sup>th</sup> CPC recommendation.
3. These orders will take effect from the date of issue of this O.M. The cases where the advances have already been sanctioned need not be reopened.
4. In so far as persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.
5. All the Ministries/Departments are requested to bring the amendments to the notice of all its attached and subordinate offices for their information.

Hindi version of this O.M. is enclosed.

  
(Pankaj Hazarika)  
Director, E.II(A)

To

All the Ministries/Departments of the Government of India, etc.

Copy (with usual number of spare copies) forwarded to C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

AMENDMENT TO COMPENDIUM OF RULES ON ADVANCES TO  
GOVERNMENT SERVANTS, 2005.

Sl.No	Name of Advance	GoI Decision on 7 <sup>th</sup> CPC recommendations
1.	Bicycle Advance	Abolished
2.	Warm Clothing Advance	Abolished
3.	Advance of Pay on Transfer	Abolished
4.	Festival Advance	Abolished
5.	Natural Calamity Advance	Abolished
6.	Advance of Leave Salary	Abolished
7.	Advance for Law Suits	Abolished

सं. 12(1)/ई-II(ए)/ 2016

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली 7 अक्टूबर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अग्रिम प्रदान किया जाना - सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों - सरकारी कर्मचारियों के अग्रिमों से संबंधित नियमों का सार संग्रह के नियमों में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अग्रिमों के संबंध में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, संलग्न अनुबंध के अनुसार सभी ब्याज मुक्त अग्रिमों को इस अपवाद के साथ समाप्त कर दिया गया है कि चिकित्सीय उपचार, मृतक के परिवार के लिए यात्रा भत्ते, दौरे पर या स्थानांतरण पर यात्रा भत्ते और छुट्टी यात्रा रियायत के लिए ब्याज मुक्त अग्रिम जारी रखे जाएंगे।

2. इसके अतिरिक्त, पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से हिन्दी प्रशिक्षण के लिए अग्रिम भी, जिसका उल्लेख सरकारी कर्मचारियों के अग्रिमों से संबंधित नियमों के सार-संग्रह में नहीं किया गया है, 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में समाप्त कर दिया गया है।

3. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे। जिन मामलों में अग्रिमों को पहले से ही मंजूरी दे दी गई है, उन पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

4. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे इन संशोधनों की जानकारी अपने सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को दें।

Ychuj

( पंकज हजारिका )

निदेशक, ई-II(ए)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, आदि।

मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, आदि को प्रति (अतिरिक्त प्रतियों सहित) प्रेषित।

सरकारी कर्मचारियों के अग्रिमों से संबंधित नियमों का सार-संग्रह, 2005 में संशोधन

क्र. सं.	अग्रिम का नाम	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार का निर्णय
1.	साइकिल अग्रिम	समाप्त कर दिया गया
2.	गर्म कपड़ा अग्रिम	समाप्त कर दिया गया
3.	स्थानांतरण पर वेतन अग्रिम	समाप्त कर दिया गया
4.	त्यौहार अग्रिम	समाप्त कर दिया गया
5.	प्राकृतिक आपदा अग्रिम	समाप्त कर दिया गया
6.	छुट्टी वेतन अग्रिम	समाप्त कर दिया गया
7.	मुकदमों के लिए अग्रिम	समाप्त कर दिया गया

No. 12(1)/E.II(A)/2016  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Expenditure  
...

New Delhi, the 7<sup>th</sup> October, 2016

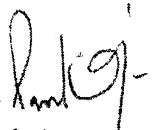
OFFICE MEMORANDUM

Subject: Grant of advances - Seventh Pay Commission recommendations- Amendment to Rules 21(5) of Compendium of Rules on Advances to Government Servants.

The undersigned is directed to say that in pursuance of the decision taken by the Government on the Seventh Pay Commission's recommendations relating to advances, the existing provisions of Compendium of Rules on Advances - 21(5) relating to Personal Computer Advance are amended as per the amendments attached.

2. These orders will take effect from the date of issue of this O.M. The cases where the advances have already been sanctioned need not be reopened.
3. The other interest bearing advances relating to Motor Car Advance and Motorcycle / Scooter / Moped Advance will stand discontinued.
4. In so far as persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.
5. All the Ministries/Departments are requested to bring the amendments to the notice of all its attached and subordinate offices for their information.

Hindi version of this O.M. is enclosed.

  
(Pankaj Hazarika)  
Director, E.II(A)

To

All the Ministries/Departments of the Government of India, etc.

Copy (with usual number of spare copies) forwarded to C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

AMENDMENTS TO COMPENDIUM OF RULES ON ADVANCES TO  
GOVERNMENT SERVANTS, 2005

**CONDITIONS OF GRANT OF COMPUTER ADVANCE:**

**Rule 21(5)**

Advance	Quantum	Eligibility Criteria
Personal Computer Advance	Rs.50,000 or actual price of PC, whichever is lower.	All government employees

- (ii) The Computer advance will be allowed maximum five times in the entire service.

सं. 12(1)/ई.II(ए)/2016

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

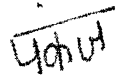
नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्टूबर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अग्रिम प्रदान किया जाना - सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों - सरकारी कर्मचारियों के अग्रिमों से संबंधित नियमों का सार-संग्रह के नियम 21(5) में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अग्रिमों के संबंध में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, पर्सनल कम्प्यूटर अग्रिम से संबंधित अग्रिमों पर नियमों के सार संग्रह के मौजूदा प्रावधानों - 21(5) में संलग्न संशोधनों के अनुसार संशोधन किए जाते हैं।

2. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे। जिन मामलों में अग्रिमों को पहले से ही मंजूरी दे दी गई है, उन पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
3. मोटर कार अग्रिम और मोटरसाइकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम से संबंधित अन्य ब्याज वाले अग्रिमों को समाप्त कर दिया गया है।
4. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।
5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे इन संशोधनों की जानकारी अपने सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को दें।



(पंकज हजारिका)

निदेशक, ई.II(ए)

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, आदि।

मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को प्रति (अतिरिक्त प्रतियों सहित) प्रेषित।



सरकारी कर्मचारियों के अग्रिमों से संबंधित नियमों के  
सार - संग्रह में संशोधन, 2005

कम्प्यूटर अग्रिम प्रदान किए जाने की शर्तें:

नियम 21(5)

अग्रिम	मात्रा	पात्रता मानदंड
पर्सनल कम्प्यूटर अग्रिम	50,000 रु. या पर्सनल कम्प्यूटर का वास्तविक मूल्य, जो भी कम हो	सभी सरकारी कर्मचारी।

(ii) पूरे सेवाकाल में कम्प्यूटर अग्रिम की अधिकतम पांच बार की अनुमति दी जाएगी।